



## NO FDI CONCERN FOR OTT

The Govt has allayed the concerns of the OTT players and stated that the FDI limit of 26% with government approval route would not apply to the OTT platforms that are just hosting the digital feed of a TV news channel.

“TV news channels granted permission under the Uplinking and Downlinking Guidelines, 2022 (and the earlier Guidelines of 200W and 20 11) Of the Ministry of Information & Broadcasting and their entities operating the digital news content are already covered by FDI policy of the Central Government. Accordingly, when an OTT platform hosts the digital feed of a TV news channel (granted permission under the extant Guidelines), the stipulation of FDI limit of 26% with Government approval route would not apply to the OTT platform for the mere activity of hosting such feed,” read a statement issued by the Deputy Director (Digital Media), MIB.



## SOCIAL MEDIA COS UNDER RADAR

The government has set a platform to look into complaints against social media companies and the complaints will be further escalated to three sub-committees.

Companies like Google and Meta will be asked to be part of the platform for addressing user complaints. They will also be required to respond to grievances on the portal.



## ZEE SEES INCREASE IN TAMIL VIEWERS ON OTT

Zee5 OTT platform has seen a surge in viewership and has clocked a 54% increase in viewer base and a 63% increase in active user base in the Tamil region in the last one year.

## ओटीटी के लिए कोई चिंता की बात नहीं एफडीआई

सरकार ने ओटीटी कंपनियों की चिंताओं को दूर किया है और कहा है कि सरकारी अनुमोदन के मार्ग के साथ 26% की एफडीआई सीमा उन ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर लागू नहीं होगी जो सिर्फ एक टीवी समाचार चैनल के डिजिटल फीड की मेजबानी कर रहे हैं।

एमआईबी के उप-महानिदेशक (डिजिटल मीडिया) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 'टीवी समाचार चैनलों को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशानिर्देश, 2022 (200डब्ल्यू और 2011 के पहले दिशानिर्देश) के तहत अनुमति दी गयी है और डिजिटल समाचार सामग्री का संचालन करने

वाली उनकी संस्थाएँ पहले से ही केंद्र सरकार की एफडीआई नीति द्वारा कवर की गयी हैं। तदनुसार जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म एक टीवी न्यूज चैनल (मौजूदा दिशानिर्देश के तहत अनुमति दी गयी) के डिजिटल फीड को होस्ट करता है तो सरकारी मार्ग के साथ 26 प्रतिशत की एफडीआई सीमा की शर्त ऐसी मेजबानी की गतिविधि के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए लागू नहीं होगी।

## निगरानी के तहत सोशल मीडिया कंपनियां

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और शिकायतों को आगे तीन उप-समितियों तक पहुंचाया जायेगा।

उपयोगकर्ता शिकायतों को दूर करने के लिए गुगल और मेटा जैसी कंपनियों को प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए कहा जायेगा। उन्हें पोर्टल पर शिकायतों का जवाब देना भी आवश्यक होगा।

## जी ओटीटी पर तमिल दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी

जी5 ओटीटी प्लेटफॉर्म के दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है और पिछले एक साल में तमिल क्षेत्र में दर्शकों के आधार में 54% की वृद्धि और सक्रिय उपयोगकर्ता आधार में 63% की वृद्धि देखी गयी है।



Zee5 made its entry into the Tamil entertainment industry last year with a slate of Tamil originals.

Manish Kalra, Chief Business Officer, Zee5 India, said, "We, at Zee5, are happy to receive an encouraging response at the very onset of our journey in this region. The advantages of following a consumer-first approach in curating the Tamil slate has worked successfully for us."

Siju Prabhakaran, Chief Cluster Officer – South, Zee Entertainment Enterprises, said, "We have sojourned in the OTT space with a very confident outlook and understanding of the market. Our creative experimentation this year has had us pushing the envelope and presenting unconventional narratives that transcended traditional barriers of what people expect on OTT."

## WHY DID DISNEY LET GO OF HBO

The story behind the deal with Disney+Hotstar, HBO souring was HBO had asked for a sum that Disney felt was not viable. HBO had asked for a sum of \$50 million for five years for the contract to be renewed

Disney let go of HBO as the subscriber base for its content is niche and is relatively low on the platform, so it does not justify the asking price.

Disney+ Hotstar is not going to have any impact on the platform's subscription base, as the number of people viewing that content is almost negligible on the OTT platform.

Hotstar has been streaming HBO original shows since January 2016. In December 2015, Disney Star had struck an exclusive tie-up with HBO.

Disney CEO Bob Iger recently announced the plan to cut \$5.5 billion in costs. This cost-cutting included about \$3 billion in non-sports-related content and \$2.5 billion in non-content-related costs. ■



जी5 ने तमिल मनोरंजन उद्योग में पिछले साल तमिल मूल की सामग्री के साथ प्रवेश किया।

जी5 इंडिया के मुख्य व्यवसाय अधिकारी मनीष कालरा ने कहा 'जी5 में हम इस क्षेत्र में अपनी यात्रा की शुरुआत में उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त करके खुश हैं। तमिल सामग्री को क्यूरेट करने में उपभोक्ता पहले दृष्टिकोण का पालन करने के फायदे हमारे लिए सफ़तापूर्वक काम कर रहे हैं।

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के दक्षिण के लिए मुख्य क्लस्टर अधिकारी सिजू प्रभाकरन ने कहा 'हम ओटीटी क्षेत्र में एक बहुत ही आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण और बाजार की समझ के साथ आये हैं। इस साल हमारे रचनात्मक प्रयोग ने हमें दायरे को आगे बढ़ाने और अपरंपरागत आख्यानों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है, जो ओटीटी पर लोगों की अपेक्षा के पारंपरिक अवरोधों को पार करता है।

## डिज्नी ने एचबीओ को क्यों जाने दिया

डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एचबीओ के साथ खट्टे सौदे के पीछे की कहानी यह थी कि एचबीओ ने एक राशि की मांग की थी जो डिज्नी को लगा कि यह व्यवहार्य नहीं है। एचबीओ ने अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए पांच साल के लिए 5 मिलियन डॉलर की मांग की थी। डिज्नी ने एचबीओ को जाने दिया क्योंकि इसकी सामग्री के लिए सब्सक्राइबर आधार विशिष्ट और प्लेटफॉर्म पर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए यह मांग की गयी कीमत को उचित नहीं ठहराता है।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर आधार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उस कंटेंट को देखने वालों की संख्या लगभग नगण्य है। हॉटस्टार जनवरी 2016 से एचबीओ के मूल शो को स्ट्रीम कर रहा है। दिसंबर 2015 में डिज्नी स्टार ने एचबीओ के साथ एक विशेष समझौता किया था।

डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने हाल ही में लागत में 5.5 अरब डॉलर की कटौती की योजना की घोषणा की। इस लागत कटौती में गैर-खेल-संबंधित सामग्री में 3 बिलियन डॉलर और गैर-सामग्री-संबंधित लागतों में 2.5 बिलियन डॉलर शामिल थे। ■